



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 04, 1936

No. 620]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 04, 1936

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 838(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध अधीक्षक (मुद्रण) और सहायक (मुद्रण) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में अधीक्षक (मुद्रण) और सहायक (मुद्रण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, अधीक्षक (मुद्रण) और सहायक (मुद्रण), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अधीक्षक (मुद्रण)	2* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड 2 9300-34800/- धन 4600/- ग्रेड वेतन	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय समझा गया है, या किसी अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री। (ii) किसी सरकारी मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का, विशेषतः विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों के प्रूफों का तीन वर्ष का अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>वांछनीय :</p> <p>किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय समझा गया है, या किसी अन्य संस्थान या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक (मुद्रण), जिसने 9300-34800/- रुपए के वेतन बैंड 2 धन 4200/- ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्निश्चित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्निश्चित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टिकरण समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन), विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>(उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p> <p>प्रशिक्षण : प्रोन्नति के लिए, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, विधायी मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा विधायी प्रारूपण में तीन मास का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा। ऐसे व्यक्तियों को, जो दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने हैं, ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण करने से छूट होगी : परंतु ऐसे व्यक्तियों पर भी, जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पहले प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक (मुद्रण)	5* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2 - 9300-34800/- धन 4200/- ग्रेड वेतन	चयन	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उनके अधीन स्थापित या निगमित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संस्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय समझा गया है, या किसी अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री।</p> <p>(ii) किसी सरकारी मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का, विशेषतः विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों के प्रूफों का, दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि</p>	नहीं	दो वर्ष	<p>(i) वीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। वांछनीय : (i) किसी सरकारी मुद्रणालय या पंजीकृत समाचारपत्र कार्यालय में अंग्रेजी कापी-होलिडिंग/प्रूफ रीडिंग में अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिंदी एक विषय के रूप में या परीक्षा माध्यम के रूप में हाई स्कूल पास।			
--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : प्रूफ रीडर, जिसने 5200-20200/- रुपए के वेतन बैंड 1 धन 2800/- ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्निश्चित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्निश्चित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p> <p>प्रशिक्षण : प्रोन्नति के लिए, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, विधायी मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा विधायी प्रारूपण में पन्द्रह दिन का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा। ऐसे व्यक्तियों को, जो दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने हैं, ऐसा प्रशिक्षण पूर्ण करने से छूट होगी। परंतु ऐसे व्यक्तियों पर भी, जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से पहले प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा कि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टिकरण समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —अध्यक्ष संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य उप सचिव (प्रशासन), विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय — सदस्य 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. ए-12018/1/2012-प्रशा. 1 (वि.वि.)]

शरदा जैन, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2014

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department) Group 'B' posts Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Superintendent(Printing) and Assistant(Printing), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Superintendent (Printing) and Assistant (Printing) in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Superintendent (Printing) and Assistant (Printing), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Superintendent (Printing)	2* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognised University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government.</p> <p>(ii) Three years' experience of proof reading, particularly proofs of Bills, Acts, Ordinances in a Government Press.</p> <p>Desirable :</p> <p>Degree in Law from a recognised University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No	Two years for direct recruits	Promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Assistant (Printing) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with five years' regular service in Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the</p>	<p>Group 'B', Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman; 2. Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 3. Deputy Secretary (Administration), Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member. 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.</p>

<p>revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Training :</p> <p>Successful completion of three months' Basic Course in Legislative Drafting by the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) , Legislative Department, Ministry of Law and Justice shall be mandatory for promotion.</p> <p>Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training:</p> <p>Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of the Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of the Departmental Promotion Committee.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant (Printing)	5* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band – 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Selection.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential :</p> <p>(i) Degree from a recognised University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government.</p> <p>(ii) Two years' experience of proof reading, particularly proofs of Bills, Acts, Ordinances in a Government Press.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No	Two years	<p>(i) Twenty percent by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) eighty percent by direct recruitment.</p>

Desirable : (i) Experience of English Copy-holding or proof reading work in a Government printing Press or a registered Newspaper office. (ii) Passed High School with Hindi as a subject or as a medium of Examination from a recognised Board.			
(11)	(12)		(13)
Promotion: Proof Reader with six years' regular service in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Training : Successful completion of Appreciation course for fifteen days in the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR), Legislative Department, Ministry of Law and Justice shall be mandatory for promotion. Those persons who are due to retire within two years shall be exempted from completion of such training: Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of the Departmental Promotion Committee shall also be considered subject to the condition that the required training shall be completed within one year of the date of meeting of the Departmental Promotion Committee.	Group 'B' , Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :— 1. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman; 2. Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member; 3. Deputy Secretary (Administration), Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.		Not applicable.

[F. No. A. 12018/1/2012-Admn.I (LD)]

SHARDA JAIN, Jt. Secy. and Legislative Counsel